[Shri Xavier Arakal]

agencies at the Indian airports. At present 36 international airlines fly more than 12·5 million passengers and lift 21,000 tonnes of cargo every year through the international airports of Bombay, Delhi, Calcutta and Madras alone. It is quite evident that at present the International Airport Authority of India cannot cope with the various multifarious problems and complaints, while it is made accountable by law. This paradox has tobe removed immediately for the safety and security of the passengers, aircrafts and airports. It seems there are 16 Government agencies, 4 airline agencies, 16 commercial concerns, 3 contractors not under IAAI, 5 contractors with IAAI, 4 B.P.E. agencies functioning within these airport areas. This reveals the tremendous, complicated, disorganised and dis-coordinated work of the airports.

It is important that there should be one agency as the supreme functional authority to which all other agencies or units are made accountable and subordinate. If this is not effected immediately, I am afraid many more tragic incidents will be repeated. Therefore, I urge upon the Government to constitute a high level committee immediately, in order to vest the supreme functional authority in the International Airports Authority of India for the security, safety and efficient, organic functioning of the airport ion India.

(xii) Need to provide same facilities and promotional avenues to University teachers throughout the Country

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस प्रकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों के पदों पर अध्यापकों को रोटेशन में नियुक्त किया जाता है उसी प्रकार देश के सभी विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों को शिक्षकों के अध्यापकगण उन सुविधाओं से वंचित हैं। अतः सरकार से मेरी मांग है कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को समान सुविधाएं एवं पदोन्नति आदि के समान अवसर प्रदान किए जाएं।

(xiii) Need to improve the telecommunication facilities in Madhya Pradesh and to introduce modern telecommunication techniques in the Country

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश में दूर संचार प्रणाली को अधिक कार्यक्रम बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जाना चाहिए। मध्यप्रदेश में दूर संचार का विस्तार निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। वर्ष 1983-84 की अवधि में 70 दूरभाष केन्द्रों की क्षमता विस्तार का लक्ष्य निश्चित किया गया था किन्तु विगत वर्ष के लक्ष्य का भी अब तक 29 दूरभाष केन्द्रों का विस्तार है जिसमें उज्जैन, सहित भोपाल, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर के दूरभाष केन्द्र सम्मिलित हैं। विस्तार कार्य नहीं किया जा सका है। उज्जैन के दूरभाष केन्द्र का विस्तार विगत चार वर्षों से कार्य नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं तो उज्जैन, इन्दौर भोपाल सहित प्रमुख नगरों में दूरसंचार व्यवस्था को कार्यक्षम बनाने की आवश्यकता है। आलोट-जावरा को ताल से जोड़ा जाना चाहिए। आलोट से ताल के बीच उपलब्ध टेलीफोन लाइन को सुधार कर यह किया जा सकता है। तराना से माकड़ोन के बीच टेलीफोन सेवा में सुधार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बड़नगर खाचरोद, आलोट, महिदपुर और तराना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष प्रणाली को कार्यक्षम बनाने के उपाय किए जाने चाहिएं।

अतएव मेरा संचार मंत्रालय से आग्रह है कि देश में दूर संचार प्रणाली को आधुनिकतम तकनीकी अनुरूप विकसित कर कार्यक्षम बनाए जाए। साथ ही मध्य प्रदेश